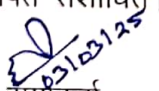
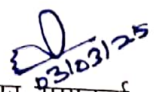


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-21/2011-12

(58/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-बैजनाथ भगत
आदेश

देश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-58/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-खपड़ाजोला के खाता सं०-42/31 के दाग सं०-178 अंतर्गत रकवा-00-04-00धूर भूमि का विपक्षी बैजनाथ भगत पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-97/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। कई नोटिस के बाद विपक्षी के पुत्र भरत प्रसाद भगत के द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक-03.07.2014 को एक आवेदन दाखिल कर कहा गया कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है तथा इस मामले में उचित निर्णय पारित करने का अनुरोध किया गया। उनके आवेदन से स्पष्ट है कि इस वाद के विपक्षी बैजनाथ भगत की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद विपक्षी कभी भी इस न्यायालय में न तो स्वयं और न ही अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए और न ही कोई पैरवी की गई। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। स्पष्ट है कि विपक्षी की इस वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गई है एवं इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि विपक्षी को किस आधार पर प्राप्त हुआ एवं पंजी-11 में जमाबंदी किस आधार पर सृजित की गई है इस संदर्भ में कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। स्पष्टतः राजस्व पंजी-11 में विपक्षी के नाम से सृजित जमाबंदी, अवैध रूप से सृजित है, जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी बैजनाथ भगत, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	